S.No.	State	1996 (upto 8.6.96)
23.	Tripura	0
24.	Uttar Pradesh	8
25.	West Bengal	—
26.	A.&.N. Islands	0
27.	Chandigarh	
28.	Dadra & Nagar Haveli	0
29.	Daman & Diu	0
30.	Delhi	122
31.	Lakshadweep	0
32.	Pondicherry	0
	Total	1019

— = Information not received
0 = NIL

राष्ट्रीय कैंसर कार्यक्रम हेतु धनराशि का उपयोग

1008. श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले दशक के दौरान कार्यान्वित राष्ट्रीय कैंसर कार्यक्रम के लिये निर्धारित और स्वीकृत धनराशि के बड़े भाग का वास्तव में उपयोग नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु कोई कार्रवाई की गयी है या किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) पिछले दस वर्षों में धन का कम उपयोग इसलिए हुआ क्योंकि अनेक संस्थान कोबाल्ट चिकित्सा यूनिटों की स्थापना नहीं कर सके क्योंकि यूनिट की कुल लागत बहुत अधिक हो गई अथवा राज्य सरकार/संस्थानों द्वारा अपेक्षित अवसंरचना तथा कर्मचारी सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। कुछ मामलों में राज्य सरकारों ने संबंधित संस्थानों को केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि विमुक्त नहीं की।

(ग) और (घ) कोबाल्ट यूनिटों के लिए अनुदान की राशि में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई है ताकि सहायता का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सके। सेवाओं की अधिक उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक आधार पर रोगियों का शुरू में पता लगाने तथा उपचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोगियों का शीघ्र पता लगाने के लिए जिला स्तर की योजनाएं शुरू की गई हैं। कार्यक्रम के आवश्यक प्रबोधन तथा राज्य सरकारों के सुग्राहीकरण के परिणामस्वरूप बेहतर कार्यान्वयन हुआ है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण ने कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की प्रगति के प्रबोधन, मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

Indian Banks and FIS figuring in dossier of Income Tax Department

1009. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Indian Banks and Financial institutions figure prominently in a confidential dossier of the Income Tax department among the defaulters;

(b) if so, the details thereof;

(c) the action taken by Government to recover this outstanding amount from the Indian Banks and institutions; and

(d) the time limit fixed for recovery of this outstanding amount?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The Income Tax Department monitors the cases involving arrears of tax particularly in bigger cases. Indian banks and financial institutions also appear in such lists prepared by the Department.

(b) List of Indian banks and financial institutions against whom income-tax demand exceeding rupees one crore remained outstanding as on 31.3.1996, is given in the annexed statement (see below).

(c) High priority is given to the work of collection/reduction of arrear demand, and appropriate administrative, legal and other meausres are taken to recover the